तेरह साल विकास के : बढ़ते हुए विश्वास के

प्रमुख आंकड़े–

– वर्ष 2003 में बजट लगभग 7 हजार करोड़ था जो अब 78 हजार करोड़ रू.से अधिक

– प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 10 हजार रू. थी, जो अब बढ़कर 82 हजार रू

– प्रदेश में शासकीय, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 4,732 मेगावॉट से बढ़कर 22,764 मेगावाट

– विद्युत पम्पों की संख्या 72 हजार से बढ़कर 4 लाख

– विद्युत उपभोक्ता 18 लाख से बढ़कर 42 लाख

– प्रति व्यक्ति विद्युत खपत, 350 यूनिट से बढ़कर 1724

– प्रदेश में निर्मित सिंचाई क्षमता 26.78 प्रतिशत थी, जो अब बढ़ कर 34.20

– शिशु मृत्यु दर 63 से घटकर 46 प्रति एक हजार

– मातृ मृत्यु दर प्रति लाख 365 से घटकर 221

– कुपोषण 52 प्रतिशत से घटकर 30 प्रतिशत

– एक दशक से भारत की औसत दर 3.97 प्रतिशत है, जबकि छत्तीसगढ़ की 6.8 प्रतिशत।

– अधोसंरचना क्षेत्र में तो क्रांति आ गई है, जिसके कारण सड़क, पुल–पुलिया, रेलवे लाइन, टेलीकॉम, बिजली आदि सम्पर्क साधनों के साथ अस्पताल, स्कूल, आंगनवाड़ी जैसी तमाम सुविधाओं का जबरदस्त विकास हुआ है।

– पहले छत्तीसगढ़ पिछड़ा राज्य कहलाता था लेकिन अब सर्वाधिक औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाला राज्य

13 साल 13 विशेष उपलब्धियां–

1. मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना– खाद्य एवं पोषण सुरक्षा कानून बनाने में अव्वल/58 लाख 80 हजार परिवारों को खाद्यान्न सहायता– एक रू. किलो चावल प्रति सदस्य 7 किलो प्रतिमाह, आयोडीनयुक्त नमक, चना एवं दाल वितरण

– पीडीएस– देश की आदर्श/पारदर्शी सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसानों को

2. शून्य ब्याज दर पर ऋण– ऋण वितरण की राशि 150 करोड़ रू. से बढ़कर लगभग 3 हजार करोड़ रू.

– समर्थन मूल्य पर धान खरीदी– विगत 13 वर्ष में 5 करोड़ 60 लाख मी.टन धान खरीदी, 53 हजार करोड़ रू. का भुगतान

3. मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना/108 संजीवनी एक्सप्रेस/102 महतारी एक्सप्रेस

4. तेन्दूपत्ता संग्रहण– संग्रहण पारिश्रमिक 350 रू. से बढ़ाकर 1500 रू. प्रति बोरा, पारिश्रमिक और बोनस मिलाकर 13 वर्षों में 26 सौ करोड़ रू. का वितरण, अन्य वनोपजों इमली, चिरौंजी गुठली, महुआ, साल बीज, लाख की समर्थन मूल्य पर खरीद से 71 करोड़ रू. का भुगतान

– तेन्दूपत्ता संग्राहकों को निःशुल्क चरणपादुका वितरण– 13 लाख संग्राहकों को निःषुल्क चरणपादुका वितरण पर 140 करोड़ रू. तथा महिलाओं को साड़ी वितरण पर 34 करोड़ रू. व्यय

5. सरस्वती सायकल योजना– हाईस्कूल स्तर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा बीपीएल परिवारों की बालिकाओं को निःषुल्क सायकल प्रदाय, दर्ज संख्या 65 से बढ़कर 93 प्रतिशत

6. मुख्यमंत्री उच्च शिक्षण ऋण ब्याज अनुदान– गरीब परिवारों के महाविद्यालयीन छात्र–छात्राओं को एक प्रतिशत की दर से 4 लाख रू. तक का ऋण/नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विद्यार्थियों को शून्य ब्याज दर पर ऋण

7. बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा–स्कूल से लेकर कॉलेज तक इंजीनियरिंग और पॉलीटेक्निक में पढ़ने वाली छात्राओं को शिक्षण शुल्क से माफी

8. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना– सामूहिक विवाह का आयोजन प्रशासन के सहयोग से, प्रत्येक बालिका के विवाह पर 15 हजार रू. की सहायता/लगभग 67 हजार कन्याओं का विवाह

9. मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना– लगभग 2 लाख वरिष्ठजनों को निःशुल्क तीर्थस्थलों की यात्रा। मुझे बुजुर्गों ने बेटा माना और मैंने बेटे का फर्ज निभाया।

10. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना– 25 लाख महिलाओं को मात्र 200 रू. की पंजीयन राशि पर निःशुल्क गैस चूल्हा सहित कनेक्शन आदि देने का लक्ष्य, अब तक 4 लाख महिलाएं लाभान्वित

11. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2022 तक सबको घर देना है।

12. सौर सुजला योजना के अंतर्गत 51 हजार किसानों को सोलर सिंचाई पम्प, 5 हजार, 10 हजार व 15 हजार रूपए में देंगे।

13. कौशल विकास/उच्च शिक्षा– कौशल उन्नयन का अधिकार युवाओं का देने हेतु कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य। देश में कौशल उन्नयन प्रशिक्षण के लक्ष्य का 15 प्रतिषत से अधिक सिर्फ छत्तीसगढ़ द्वारा पूरा करने का लक्ष्य। सभी 27 जिलों में लाइवहलीहुड कॉलेज बनाए हैं।

– छत्तीसगढ़ में आईआईटी, एनआईटी, एम्स, आईआईएम, ट्रिपल–आईटी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जैसी समस्त संस्थाओं की स्थापना

– मेडिकल कॉलेज 2 से बढ़कर 10, जिसमें से 3 निजी

– इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या 12 से बढ़कर 49

छत्तीसगढ़ में सड़क नेटवर्क

– बारह वर्षों में 59,136 कि.मी. सड़कों का निर्माण और उन्नयन किया गया।

– 852 वृहद, 337 मध्यम पुल और 23,206 पुलियों का निर्माण किया गया।

– 15 रेल्वे ओव्हर–ब्रिज तथा अण्डर–ब्रिज का निर्माण।

– 15 बायपास मार्गों का निर्माण पूर्ण।

– एडीबी अन्तर्गत 1005 कि.मी. के 18 मार्ग पूर्ण।

– नाबार्ड योजना अन्तर्गत 459 सड़कें और 174 पुल–पुलियों का निर्माण।

– कारीडोर योजना अन्तर्गत 2,230 कि.मी. की 6 मार्गों का निर्माण पूर्ण।

– एल.डब्ल्यू.ई. योजना के अन्तर्गत 2,905 करोड़ की लागत से 2,021 कि.मी. की 19 सड़कों का कार्य पूर्ण, 21 कार्य प्रगति पर।

– एन.एस.डी.पी.–4 के तहत 1,006 कि.मी. की सड़क की कुल लागत 5,500 करोड़ रू. की स्वीकृति, 557 कि.मी. सड़क पर कार्य प्रारंभ लागत 3,300 करोड़।

– एन.एस.डी.पी.–4 के तहत 1,000 कि.मी. की सड़क की स्वीकृति हेतु प्रस्तावित लागत 5,000 करोड़ रू.।

– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 12 वर्षों में 6,788 करोड़ रू. की लागत से 23,708 किलोमीटर की सड़कें पूर्ण।

– मुख्यमंत्री ग्राम सड़क विकास योजना के अन्तर्गत 1,772 करोड़ रू. की 3,737 कि.मी. की 1157 सड़कें स्वीकृत। 2,415 कि.मी. की 811 सड़कें पूर्ण।

– मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के अन्तर्गत 598 करोड़ की लागत से 1,290 कि.मी. की 4,477 गली का निर्माण पूर्ण।

छत्तीसगढ़ में रेलवे नेटवर्क

- वर्ष 2000 में 1187 कि.मी. रेल लाइनें बिछाई गई थी, वहीं वर्ष 2016 में 1733 कि.मी. हो गई है।
- भारतीय रेलवे के 150 वर्षों के इतिहास में छत्तीसगढ़ में मात्र 1187 कि.मी. रेलवे लाइनें निर्मित हो पाई थीं।
- छत्तीसगढ़ सरकार ने विशेष पहल करते हुए सार्वजनिक उपक्रमों के साथ रणनीतिक भागीदारी करते हुए रेलवे सुविधाविहीन अंचलों में रेलवे नेटवर्क विकसित करने की कार्ययोजना बनाई।
- राज्य सरकार की विशेष पहल से प्रदेश के पूर्वी तथा पूर्वी–पश्चिमी अंचल में 311 किलोमीटर रेलवे लाइनें बनाने का काम शुरू हुआ।
- ईस्ट–कॉरिडोर के अन्तर्गत खरसिया–धरमजयगढ़–कोरबा– 180 कि.मी. तथा ईस्ट–वेस्ट कॉरिडोर के अन्तर्गत गेवरा से पेण्ड्रारोड तक 131 कि.मी. रेलवे लाइन बनाने का काम प्रगति पर है।
- राज्य के दक्षिण क्षेत्र में दल्लीराजहरा से जगदलपुर के बीच 235 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क तैयार किया जा रहा है।
- इसके अलावा राज्य के मध्य–क्षेत्र में रेल यातायात के दबाव को सुगम बनाने और सरगुजा अंचल में भी रेलवे लाइन का विस्तार करने की दिशा में 762 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क के विकास की सहमति बनी है।
- रायपुर–बलौदाबाजार–झारसुगड़ा (310 कि.मी.), अंबिकापुर–बरवाडीह (182 कि.मी.), डोंगरगढ़–खैरागढ़–कवर्धा–मुंगेली–कोटा (270 कि.मी.) रेलवे लाइनों के विकास हेतु रेल मंत्रालय के साथ 'ज्वाइंट वेंचर' बनाया गया है।
- इसके अलावा मुंबई–खड़गपुर ईस्ट–वेस्ट फ्रंटियर रेल कॉरिडोर भी छत्तीसगढ़ से होकर गुजरेगा, जो केन्द्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है।

छत्तीसगढ़ में विमानन

- प्रदेश में लम्बे समय से एक विमानतल माना–रायपुर में ही है, जो राज्य के बाहर आवागमन के लिए हवाई सुविधा उपलब्ध कराता है।
- इस विमानतल को अन्तरराष्ट्रीय स्तर के एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने हेतु 'रन–वे' विस्तार का कार्य प्रगति पर है।

- वैकल्पिक स्थानों के लिए प्रदेश की न्यायिक राजधानी बिलासपुर, नई आर्थिक औद्योगिक गतिविधियों के केन्द्र, प्रदेश के प्रमुख आदिवासी बहुल क्षेत्र जगदलपुर में हवाई अड्डों का विस्तार किया जा रहा है, ताकि भविष्य में नियमित उड़ानें शुरू हो सकें।
- अम्बिकापुर, बलरामपुर में हवाई–पट्टी निर्माण का कार्य पूर्ण। जहां छोटे विमानों के लैंडिंग की सुविधा उपलब्ध।
- दंतेवाड़ा तथा बीजापुर में नई हवाई पट्टी का निर्माण प्रस्तावित।
- भारत सरकार के नवीन नागरिक उड्डयन नीति में शामिल रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम अन्तर्गत बिलासपुर, जगदलपुर, अम्बिकापुर, रायगढ़, कोरबा, बलरामपुर एवं जशपुर में एयरपोर्ट विकसित कर नियमित विमान सुविधा द्वारा राज्य के नागरिकों को सस्ती वायु सेवा उपलब्ध कराने की महत्वाकांक्षी योजना को मूर्तरूप प्रदान करने राज्य सरकार प्रयासरत है।

छत्तीसगढ़ में टेलीकॉम

- वर्ष 2000 में मोबाइल/लैंडलाइन कनेक्शन 2 लाख 80 हजार से बढ़कर वर्ष 2016 में 1 करोड़ 68 लाख 57 हजार 480 हो गई है।
- वर्ष 2000 में लैंडलाइन कनेक्शन वर्ष 2016 में 2 लाख 80 हजार से घटकर 1 लाख 92 हजार 867 हो गई है।
- वर्ष 2000 में मोबाइल कनेक्शन नहीं थी लेकिन वर्ष 2016 में 1 करोड़ 66 लाख 64 हजार 613 कनेक्शनधारी हो गए हैं।
- छत्तीसगढ़ में टेली–डेन्सिटी 65.92 है, जबकि राष्ट्रीय औसत 80.44 है।
- 'नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क' (एनओएफएन) प्रोजेक्ट के तहत बीएसएनएल द्वारा दिसम्बर 2016 तक 2,115 ग्राम पंचायतों को जोड़े जाने का लक्ष्य है।
- इस परियोजना के तहत अन्य 1894 ग्राम पंचायतों को मार्च 2017 तक जोड़ने का लक्ष्य है।
- बस्तर एवं नक्सल प्रभावित अंचल में 146 नए मोबाइल टॉवर स्थापित किए गए हैं।
- छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश के प्रमुख आदिवासी अंचल बस्तर संभाग के 7 जिलों के लिए 'बस्तर नेट' परियोजना शुरू की गई है।
- 'बस्तर नेट' के तहत 40 करोड़ रू. की लागत से 832 किलोमीटर लम्बे 'ऑप्टिक फाइबर केबल' रिंग पद्धति से बिछाए जाएंगे।
- बस्तर की दुर्गम स्थिति तथा कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में मोबाइल तथा इंटरनेट से पहुंच तथा सम्पर्क बनाने में 'बस्तर नेट' की बड़ी भूमिका होगी।

- छत्तीसगढ़ सरकार की धारणा है कि 'बस्तर नेट' बस्तर का डिजिटल हाइवे होगा, जो पहुंचविहीन क्षेत्रों में भी आसान पहुंच के माध्यम से ज्ञान आधारित समाज, विकास के अवसर तथा अर्थ व्यवस्था में नई क्रांति लाने में सहायक होगा।
- छत्तीसगढ़ शासन के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत कार्यरत संस्था 'छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रोमोशन सोसायटी' (चिप्स) द्वारा राज्य में 5 हजार से अधिक 'लोक सेवा केन्द्र' संचालित किए जा रहे हैं, जो 37 प्रकार की सेवाओं, ऑनलाइन दस्तावेज प्रदायगी के माध्यम बने हैं।

स्कूल शिक्षा

- प्रायमरी स्कूल 13,852 से 36,992
- मिडिल स्कूल 5,642 से 16,692
- हाईस्कूल 908 से 2,609
- हायर सेकेण्डरी स्कूल 680 से 3,715
- कुल स्कूलों की संख्या 21 हजार से बढ़कर 60 हजार, अर्थात् तिगुनी

उच्च शिक्षा

- शासकीय विश्वविद्यालय 3 से बढ़कर 8
- शासकीय महाविद्यालय 116 से 214
- इंजीनियरिंग कॉलेज 14 से 50
- शासकीय मेडिकल कॉलेज–7
- पालिटेक्निक कॉलेज 10 से 51
- शासकीय आईटीआई 61 से 163
- जिला लाइवलीहुड कॉलेज 0 से 27

कृषि

- धान उत्पादन 54 लाख मि.टन से 110 लाख मि.टन
- सिंचित क्षेत्र 25,034 हेक्टेयर से 1,42,934 हेक्टेयर
- कृषि ऋण ब्याज दर 14 प्रतिशत से 0 प्रतिशत
- कृषि ऋण प्रदाय 243 करोड़ रू. से बढ़कर 2472 करोड़ रू.

– फल उत्पादन 3.23 लाख मि.टन से 21.54 लाख मि.टन

– सब्जी उत्पादन 12.49 लाख मि.टन 56.97 लाख टन

जल एवं स्वच्छता

– हैण्डपम्पों की संख्या 1 लाख 48 हजार से 2 लाख 56 हजार

– गांवों में नल–जल परियोजना 978 से 3,230

– सतही जल परियोजना 866 से 2,994

– स्कूलों में पेयजल व्यवस्था 8,431 से 54,337

– आंगनवाड़ी केन्द्रों में पेयजल व्यवस्था 3,100 से 26,608

पीडीएस

– देश का आदर्श पीडीएस, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी की मदद से जीरो लीकेज सुनिश्चित।

– कोर पीडीएस।

प्रशासनिक विकेन्द्रीयकरण–

1. राजस्व जिले 16 से बढ़कर 27

2. राजस्व संभाग 4 से बढ़कर 5

3. तहसील 98 से बढ़कर 150

बस्तर का विकास

– हम चाहते हैं कि हमारा आदिवासी समाज अपने परंपरागत कारोबार के साथ ज्यादा आमदनी प्राप्त करे। इसलिए हमने एक ओर जहां लघु वनोपज के कारोबार से उन्हें ज्यादा लाभ दिलाने की कोशिश की है, वहीं दूसरी ओर मक्के की खेती को बढ़ावा दिया है, जिसका लाभ मिल रहा है।

– नई पीढ़ी की शिक्षा–दीक्षा को बेहतर जीवन स्तर का माध्यम बनाया है। बस्तर के बच्चे अब डॉक्टर, इंजीनियर ही नहीं बन रहे बल्कि प्रबंधन और विधि की उच्चस्तरीय पढ़ाई भी कर रहे हैं। यहां के बच्चे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस जैसी अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होंगे और बड़े प्रषासनिक पदों पर भी पहुंचेंगे। बस्तर में विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, एजुकेशन सिटी, लाइवलीहुड कॉलेज जैसी संस्थाओं की स्थापना हो चुकी है।

- बस्तर तथा दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण– मिनी केबिनेट की तरह काम करता है, जहां स्थानीय विकास की मांगों का निराकरण स्थल पर किया जाता है।

- प्रधानमंत्री मोदी जी पिछले साल बस्तर आए थे तो उन्होंने इस अंचल के विकास के लिए 24 हजार करोड़ रू. की सौगात दी थी। इस तरह बस्तर में नगरनार के अलावा एक और अल्ट्रा–मेगा स्टील प्लांट बनाया जा रहा है। एक स्टील प्लांट ने भिलाई और दुर्ग जिलों की तस्वीर बदल दी थी, तो दो स्टील प्लांट इस अंचल में निश्चित रूप से बड़ा चमत्कार करेंगे।

- बस्तर में दल्लीराजहरा–रावघाट तथा जगदलपुर रेल लाइन परियोजना के तहत दल्लीराजहरा से डौंडी तक 17 कि.मी. रेल लाइन का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। आने वाले वर्षों में हम इस रेल मार्ग को अंतागढ़, रावघाट, नारायणपुर, कोंडागांव होते हुए जगदलपुर तक बढ़ाएंगे।

- सड़कों का काम बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है, जिससे बस्तर चारों ओर से जुड़े। एल. डब्ल्यू.ई. योजना के अंतर्गत 2905 करोड़ रू. की लागत से 2 हजार किलोमीटर की 19 सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है तथा 21 कार्य प्रगति पर हैं।

- राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत धमतरी से जगदलपुर सड़क–219 कि.मी. का कार्य 1271 करोड़ रू. की लागत से, सुकमा से कोंटा सड़क–78 कि.मी., लागत 255 करोड़ रू. का कार्य, जगदलपुर से भोपालपट्टनम–73 कि.मी., लागत 250 करोड़ रू. का कार्य, भोपालपट्टनम से वारंगल–36 कि.मी., लागत 95 करोड़ रू. का कार्य प्रगति पर है।

- आगामी तीन वर्षों में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 1053 करोड़ रू. की लागत से 2,734 किलोमीटर की 458 सड़कों का निर्माण किया जाएगा।

- संभाग में 52 वृहद पुलों का निर्माण कराया जा रहा है, जिनमें से 17 पुलों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है।

- बस्तर संभाग में नक्सली गतिविधियों के कारण बाधित 153 सड़कों को पूर्ण किया जाएगा।

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेस–2 में 2245 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का प्रमुख जिला सड़क के अनुरूप उन्नयन किया जाएगा।

- बस्तर क्षेत्र में प्रस्तावित विभिन्न औद्योगिक तथा अधोसंरचना परियोजनाओं में 39 हजार करोड़ रू. के निवेश के साथ 24 हजार लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

- नक्सल प्रभावित अंचलों में 146 मोबाइल टॉवर स्थापित कर दिए गए हैं।

- जगदलपुर में 'सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल' के निर्माण हेतु बजट आवंटन कर दिया गया है।

- केन्द्र सरकार ने हमारे अमर शहीदों के साहस को सलाम करते हुए सीआरपीएफ की बस्तरिया बटालियन गठित करने का निर्णय लिया है, जिसमें यहां के युवाओं को रोजगार मिलेगा।

- बस्तर तथा सरगुजा संभागों में 'जिला काडर' बनाकर भर्ती करने का लाभ स्थानीय युवाओं को मिला है, साथ ही इस प्रक्रिया को दो साल के लिए बढ़ा दिया गया है।

- अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासियों को वन अधिकार पत्र वितरण में छत्तीसगढ़ अग्रणी रहा है। अभी तक 3 लाख 48 हजार परिवारों को अधिकार पत्र द्वारा 7 लाख एकड़ भूमि दी गई है। खेत समतलीकरण सहित खाद–बीज की निःशुल्क सुविधा दी जा रही है एवं सामुदायिक अधिकार पत्र भी दिए गए हैं।

- विगत 12 वर्षों में 1392 करोड़ रू. का संग्रहण पारिश्रमिक बांटा गया है। बोनस के रूप में 1237 करोड़ रू. वितरित किए गए हैं। इमली, चिरौंजी–गुठली, महुआ–बीज, लाख, साल–बीज की खरीदी भी हमने ढाई वर्ष पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य पर शुरू की थी, जिससे संग्रहकर्ताओं को अब तक 71 करोड़ रू. की आय हुई। तेन्दूपत्ता संग्राहकों के पैरों पर कांटे नहीं चुभें, इसके लिए उन्हें निःशुल्क चरणपादुकाएं दी जाती हैं।

- बस्तर की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यहां मोबाइल तथा इंटरनेट सेवा से पहुंच और सम्पर्क बनाने की जरूरत है, जो बस्तर के सभी सातों जिलों को एकसूत्र में जोड़े। इसलिए 'बस्तर–नेट' परियोजना शुरू की गई है, जिसके तहत 40 करोड़ रू. की लागत से 832 किलोमीटर लम्बे 'ऑप्टिकल फाइबर केबल' बिछाए जाएंगे। यह नेटवर्क 'रिंग पद्धति' से निर्मित होने के कारण वैकल्पिक मार्गों से निर्बाध मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान कर सकेगा।

- 'मुख्यमंत्री सोलर–लैंप वितरण' योजना के तहत 93 हजार से अधिक एलईडी लाइट तथा एक लाख 83 हजार सोलर एलईडी लैंप बांटे गए हैं।

नई योजनाएं–

- ग्रामीण आबादी पट्टा–45 लाख परिवारों को
- प्रधानमंत्री उज्जवला योजना–25 लाख परिवारों को
- हमर छत्तीसगढ़– 2 लाख जनप्रतिनिधियों को
- सीएससी को बैंक की तरह सक्षम बनाना
- किसानों की आय दुगनी करना
- 1 हजार 80 गांवों का विद्युतीकरण
- विद्युत उत्पादन क्षमता 35 हजार मेगावाट करने का लक्ष्य

- विद्युत के पारेषण, वितरण के सुधार के लिए 6 हजार करोड़ रूपए का निवेश
- रायपुर शहर के अधोसंरचना विकास के लिए 600 करोड़ रू. का निवेश
- सड़क निर्माण पर 25 हजार करोड़ रू. से अधिक का निवेश, 11 हजार किमी लम्बाई की 146 सड़कों का निर्माण
- 1300 किमी से अधिक रेल अधोसंरचना निर्माण में 20 हजार करोड़ रू. का निवेश

नोट बंदी

- भ्रष्टाचार, आतंकवाद और महंगाई की जड़ कालाधन है, जिस पर विमुद्रीकरण के जरिये प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी ने सीधा प्रहार किया है। यह उनका क्रांतिकारी कदम है।
- प्रधानमंत्री ने नगदी विहीन समाज अर्थात कैशलेस सोसायटी बनाने का आव्हान किया है। इससे नगद राशि का लेन देन नहीं होने पर करेंसी नोटों को जेब में लेकर घूमने की समस्या समाप्त हो जाएगी और इस प्रकार कैशलेस सोसायटी का निर्माण होगा।
- कैशलेस सोसायटी के निर्माण में प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया अभियान की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
- हम छत्तीसगढ़ में दस लाख लोगों की डिजिटल आर्मी बनाने जा रहे हैं।
- इसके लिए प्रत्येक नागरिक को डिजिटल प्रशिक्षित होना जरूरी है। यह कार्य भी आसानी से हो जाएगा। जैसे सबसे पहले जब मोबाईल फोन आया तो लोगों में उसके तरह–तरह के फीचर्स का इस्तेमाल करने का अनुभव नहीं था। आज मोबाइल फोन सबके लिए एक जरूरत बन गया है।
- छत्तीसगढ़ में हम उस स्तर पर प्रशिक्षण देने जा रहे हैं, जैसा कि आम चुनाव के संचालन के लिए दिया जाता है, जिसमें अधिकारी–कर्मचारी से लेकर मतदाता तक को यह जानकारी मिल जाती है कि उसे किस तरह से वोट डालना है और किस तरह की सुरक्षा अपनाना है।
- हमने सभी बैंकों से कहा है कि वे अपने खाताधारकों को प्रशिक्षित करें कि वे किस तरह से एटीएम, इंटरनेट से भुगतान या इससे जुड़ी विभिन्न सुविधाओं का उपयोग करें।
- राज्य शासन अपने स्तर पर भी सभी पंचायतों में सामान्य सेवा केन्द्र (कॉन सर्विस सेंटर) सी.एस.सी. या उपभोक्ता सेवा केन्द्र को सक्षम बना रहा है और इसके लिए प्रशिक्षित किए गए लोगों के माध्यम से गांव–गांव में प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है।